साप्ताहिक
शहर सत्ता
PRGI NO. CTHIN/25/A2378
सोमवार, 02 नवंबर से 08 नवंबर 2026
हम दिखाएंगे आईना...
वर्ष : 02 अंक : 35 पृष्ठ : 08 मूल्य : 5 रुपए
www.shaharsatta.com



पेज 03
महादेव सट्टे का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार



पेज 05
अवैध था 2024 का लोकसभा चुनाव

पेज 04 हॉकी की नई उड़ान, छत्तीसगढ़ की नई पहचान

छत्तीसगढ़ का 26वां स्थापना दिवस

विकसित छत्तीसगढ़ से साकार होगा विकसित भारत का संकल्प: मांडविया

नक्सलवाद की चुनौती से निकलकर शांति, विश्वास और विकास के नए युग में प्रवेश कर रहा बस्तर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव



रायपुर। छत्तीसगढ़ अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर आज से तीन दिवसीय राज्योत्सव की शुरुआत हो गई है। नवा रायपुर में हो रहे आयोजन के पहले दिन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का नाम लेते ही पहले नक्सलियों का नाम आता था। आज छत्तीसगढ़ एक टूरिज्म हब बन गया है। मल्टीनेशनल कंपनियां छत्तीसगढ़ में निवेश करना चाह रही हैं।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल में सबसे बड़ा काम नक्सलवाद का खात्मा हुआ है। यह राज्य के विकास में रोड़ा था, जिसे खत्म किया गया। खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर छत्तीसगढ़ में विकास नहीं पहुंच रहा था। डबल इंजन सरकार में यह समस्या हल हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को आत्मीय पत्र लिखकर प्रदेश के सभी भाई-बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में छत्तीसगढ़ से अपने दशकों पुराने आत्मीय संबंधों, प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नक्सलवाद के विरुद्ध मिली निर्णायक सफलता तथा विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में हो रहे व्यापक बदलावों का विशेष उल्लेख किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने पत्र में भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करते हुए कहा कि 26 वर्ष पूर्व उनके दूरदर्शी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। इस ऐतिहासिक निर्णय ने लाखों नागरिकों की दशकों पुरानी आकांक्षाओं को साकार किया और प्रदेश के विकास की नई यात्रा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ से अपने व्यक्तिगत जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि संगठन के दिनों से ही छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव रहा है। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से उन्हें अनेक बार यहां आने का अवसर मिला।

रायपुर। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प ही विकसित भारत के निर्माण को नई गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे साकार करने में छत्तीसगढ़ जैसे समृद्ध संसाधनों, गौरवशाली संस्कृति और अपार संभावनाओं वाले राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं, अधोसंरचना विकास, औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसरों के विस्तार से विकास की नई संभावनाएं साकार हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय राज्योत्सव 2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर राज्योत्सव का विधिवत शुभारंभ किया।

अटल जी ने छत्तीसगढ़ निर्माण का जो सपना देखा, वह आज हो रहा साकार : डॉ. मांडविया

केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पीछे स्थानीय जनता की आकांक्षाओं को नई पहचान देने और विकास की संभावनाओं को साकार करने की भावना थी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर प्रदेश के विकास की मजबूत नींव रखी थी। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए विकास के नए पथ पर अग्रसर है।

डॉ. मांडविया ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, समृद्ध लोकपरंपराएं, प्राकृतिक संपदा और यहां के लोगों की कर्मठता प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हैं। एक समय बस्तर की चर्चा मुख्य रूप से नक्सलवाद के कारण होती थी, लेकिन आज वहां खेल, पर्यटन, संस्कृति और विकास की नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। बस्तर की प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं। औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि विकास की इस यात्रा में अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को सहेजते हुए आगे बढ़ना आवश्यक है। जब देश के सभी राज्य अपनी विशिष्ट क्षमताओं और संसाधनों के आधार पर विकसित होंगे, तभी विकसित भारत का संकल्प पूर्ण होगा।

अटल जी ने निभाया छत्तीसगढ़ निर्माण का वादा : मुख्यमंत्री श्री साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विकास की यात्रा को स्मरण करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता से राज्य निर्माण का वादा किया था। प्रदेशवासियों ने उनके नेतृत्व पर विश्वास जताया और उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का स्वरूप प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व में निर्मित छत्तीसगढ़ आज विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। राज्य गठन के समय प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की अनेक चुनौतियां थीं। बीते वर्षों में इन क्षेत्रों में व्यापक विस्तार हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ कर गरीब परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था ने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान की। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में ऐतिहासिक सफलता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद लंबे समय तक बस्तर के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक रहा। प्राकृतिक सौंदर्य, वन एवं खनिज संपदा से समृद्ध होने के बावजूद नक्सलवाद के कारण बस्तर के अनेक क्षेत्रों तक विकास की सुविधाएं अपेक्षित रूप से नहीं पहुंच सकीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के दृढ़ संकल्प एवं मार्गदर्शन में नक्सलवाद का उन्मूलन हुआ।

समापन समारोह में आएंगे शाह



राज्योत्सव मेला स्थल को देश के अलग-अलग राज्यों से आए कारीगरों ने सजाया है। विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों में सरकारी योजनाओं, उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजना को दिखाया जाएगा। तीन दिवसीय आयोजन के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए, जबकि समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़वासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी है।

41 राज्य अलंकरण और पुरस्कार दिए जाएंगे

इस बार राज्योत्सव की थीम 'सशक्त नारी-युवा उड़ान' रखी गई है। समारोह के अंतिम दिन 41 राज्य अलंकरण और पुरस्कार दिए जाएंगे। इस बार 3 नए सम्मान दिए जाएंगे। पहली बार पंडवानी गायिका तीजन बाई, संत रविदास और चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार के नाम पर राज्य अलंकरण शुरू किया जा रहा है। समारोह में गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में अलग-अलग क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा।

सारंग टीम का प्रदर्शन अनुशासन, आपसी विश्वास, टीम भावना और उत्कृष्टता का अनुपम उदाहरण : मुख्यमंत्री



छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर नवा रायपुर का आसमान भारतीय वायु सेना के अदम्य शौर्य, साहस, अनुशासन और अद्भुत उड़ान कौशल का साक्षी बना। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज नवा रायपुर के सेंध लेक में आयोजित भारतीय वायु सेना की विश्वप्रसिद्ध सारंग एयरोबेटिक डिस्प्ले टीम के रोमांचकारी हवाई प्रदर्शन की फुल ड्रेस रिहर्सल में शामिल हुए। इस अवसर पर भारतीय वायु सेना की आकाशगंगा स्काईडाइविंग टीम, गरुड़ कमांडोज और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के जाँबाजों ने अपने साहसिक करतबों, सटीक नियंत्रण और बेहतरीन तालमेल से उपस्थित जनसमूह को रोमांचित कर दिया। आसमान में तिरंगे की मनमोहक छटा, हेलीकॉप्टरों की आकर्षक फॉर्मेशन और 'वंदे मातरम्' की गूंज ने पूरे वातावरण को देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना से सराबोर कर दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने भारतीय वायु सेना के जाँबाजों के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय वायु सेना की प्रतिष्ठित सारंग टीम का यह आयोजन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है। हमारे वायु वीरों ने जिस साहस, अनुशासन, आत्मविश्वास और सटीक समन्वय के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन किया है, वह प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणादायी है।

साप्ताहिक शहरसत्ता
हम निभाएंगे आपका...

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग मैनपाट टाइटन्स बनी चैंपियन

संस्कारधानी स्ट्राइकर्स को 4-2 से हराया



शहरसत्ता/रायपुर। भारत की पहली मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले संस्करण का खिताब छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की टीम मैनपाट टाइटन्स ने अपने नाम कर लिया। राजधानी रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में मैनपाट टाइटन्स ने सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड की टीम संस्कारधानी स्ट्राइकर्स को 4-2 गोल से पराजित कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। खिताबी जीत के साथ ही स्टेडियम आतिशबाजी और जश्न से गूंज उठा। फाइनल मुकाबले को देखने के लिए अन्य दिनों की तुलना में बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।



फाइनल मुकाबला शुरू से ही बेहद रोमांचक रहा। दोनों टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली और एक समय स्कोर 2-2 गोल की बराबरी पर पहुंच गया। मुकाबले को देखते हुए पेनल्टी शूटआउट की संभावना भी बन रही थी, लेकिन अंतिम क्षणों में मैनपाट टाइटन्स ने दो गोल दागकर मैच का रुख बदल दिया और 4-2 से जीत दर्ज कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। मैनपाट के खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले में शानदार तालमेल और खेल कौशल का प्रदर्शन किया।

लीग के समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। विशिष्ट अतिथियों में उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव, गृहमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहेब, सांसद बृजमोहन अग्रवाल तथा लीग के ब्रांड एम्बेसडर एवं पूर्व ओलंपियन सरदार सिंह उपस्थित रहे। अतिथियों ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी एवं नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। खिताब जीतने वाली मैनपाट टाइटन्स को 11 लाख रुपये की पुरस्कार राशि और विजेता ट्रॉफी प्रदान की गई, जबकि उपविजेता संस्कारधानी स्ट्राइकर्स को 6 लाख रुपये एवं उपविजेता ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए गए। संस्कारधानी स्ट्राइकर्स के अभिषेक यादव को स्टार स्ट्राइकर ऑफ द मैच, मैनपाट टाइटन्स के मोहित नायक को प्लेयर ऑफ द मैच और संदीप कुमार को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार मिला। राजधानी रॉयल्स के हिमांशु बेस्ट गोलकीपर चुने गए, जबकि संस्कारधानी स्ट्राइकर्स के आशीष तानी को हाइएस्ट गोल स्कोरर का खिताब मिला। संस्कारधानी स्ट्राइकर्स के शाहरुख अली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। उन्हें एक लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया।

खेल के मैदान में कोई हारता नहीं, या तो जीतता है या सीखता है : डॉ. मांडविया

समापन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने अपने संबोधन में कहा कि मेजर ध्यानचंद के समय से लेकर आज तक भारतीय हॉकी निरंतर आगे बढ़ रही है। हाल ही में एशियन गेम्स में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में ओलंपियन और विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी से स्थानीय खिलाड़ियों को उनके अनुभव और खेल कौशल से सीखने का अवसर मिला है।

डॉ. मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व बदलाव हो रहा है और एक मजबूत खेल इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल के मैदान में कोई हारता नहीं है, या तो जीतता है या सीखता है। उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को बधाई देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल की सराहना की। साथ ही उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की यह पहल देश के अन्य राज्यों को भी ऐसे आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी।

हॉकी लीग का आयोजन गौरव का विषय : मुख्यमंत्री

समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य और गौरव का विषय है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का ऐतिहासिक आयोजन हुआ और इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की गरिमामयी उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने विजेता एवं उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को बधाई देते हुए आयोजन से जुड़े सभी आयोजकों, सहयोगियों और प्रायोजकों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस आयोजन को प्रदेश में हॉकी को प्रोत्साहन देने और स्थानीय खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।





दिवाली से पहले केंद्र की बड़ी सौगात, टैक्स डिवोल्यूशन के 3,602 करोड़ रुपए जारी

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ को दीपावली से पहले केंद्र सरकार की ओर से बड़ी आर्थिक राहत मिली है। केंद्र ने छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन की अग्रिम किस्त जारी की है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के हिस्से में 3,602 करोड़ रुपये आए हैं। त्योहार से पहले मिली इस राशि से प्रदेश में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र से मिली इस राशि से प्रदेश के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन की अग्रिम किस्त जारी की है। इस राशि में छत्तीसगढ़ को 3,602 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे राज्य सरकार को विकास योजनाओं और जरूरी सरकारी कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। टैक्स डिवोल्यूशन के तहत केंद्र सरकार अपने पास एकत्रित किए गए करों का निर्धारित हिस्सा राज्यों को देती है। इसका उद्देश्य राज्यों को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उन्हें विकास कार्यों के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्र से मिली राशि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ को 3,602 करोड़ रुपये की राशि मिलने से प्रदेश में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को नई गति मिलेगी। उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के प्रति समस्त प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया।

नवा रायपुर में लगेगी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ की पहचान अब तक मुख्य रूप से कोयला, स्टील, सीमेंट और बिजली उत्पादन जैसे पारंपरिक उद्योगों से रही है, लेकिन आने वाले समय में प्रदेश की यह तस्वीर बदल सकती है। राज्य सरकार अब उद्योगों के नए क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है। इसमें आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, फार्मा, टेक्सटाइल और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को केवल खनिज आधारित उद्योगों तक सीमित रखने के बजाय आधुनिक तकनीक और नए कारोबार का केंद्र बनाना है। पिछले तीन वर्षों में प्रदेश को 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से कई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो चुका है। इनसे करीब पौने दो लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि नवा रायपुर को भविष्य के टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार नवा रायपुर को आधुनिक तकनीक और नए उद्योगों के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के साथ उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

रायपुर में खाद्य विभाग का छापा, 80 किलो ब्रेड और 8 बोरी मैदा जब्त

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने औचक निरीक्षण अभियान चलाया। विभाग की टीम ने शहर की एक बेकरी फैक्ट्री सहित कई मिठाई प्रतिष्ठानों में पहुंचकर जांच की। इस दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए और साफ-सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण में अस्वच्छता मिलने पर करीब 80 किलो ब्रेड और मैदे की 8 बोरियां जब्त की गईं। विभाग की इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नियंत्रक दीपक अग्रवाल अपनी टीम के साथ शहर के अलग-अलग इलाकों में निरीक्षण के लिए पहुंचे। सबसे पहले टीम ने समता कॉलोनी स्थित द ब्रेड बास्केट की फैक्ट्री का निरीक्षण किया। यहां तैयार किए जा रहे नमकीन, कुकीज और ब्रेड की गुणवत्ता की जांच के लिए नमूने लिए गए। इन सैंपल को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। टीम ने भानपुरी स्थित खत्री स्वीट्स, कमल विहार स्थित कृष्ण स्वीट्स और दावड़ा कॉलोनी स्थित अग्रवाल मिठाई वाला में भी औचक निरीक्षण किया।

महादेव सट्टे का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार

CBI की टीम ने ओमान में पकड़ा, आज रायपुर कोर्ट में पेशी



शहर सत्ता/रायपुर। महादेव ऑनलाइन बुक के नाम से सट्टा एप चलाने वाले मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कर भारत लाने में बड़ी सफलता मिली है। चंद्रकार सट्टा एप से माध्यम से 94 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रकम जुटाने का आरोप है। भारत आते ही सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और सोमवार को उसे रायपुर ले जाकर विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। चंद्राकर के वापस आने से महादेव सट्टा एप से जुड़े आरोपियों और उन्हें संरक्षण देने वाले राजनेताओं पर बड़ा खुलासा हो सकता है। एप के संचालकों से सरकारी संरक्षण देने के एवज में 508 करोड़ रुपये लेने के आरोप में घिरे हैं। ईडी और सीबीआइ दोनों इस मामले की जांच कर रही हैं।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि परिवार और सहयोगियों के साथ 2022 में भिलाई से भागने के बाद सुभाष चंद्राकर दुबई में रह रहा था और वहीं महादेव सट्टा एप का हेडक्वार्टर बना रखा था। 2023 में जांच शुरू होने और एजेंसियों का दबाव बनने के बाद वह ओमान भाग गया और वहां वानुअतु का नागरिक बताने लगा। लेकिन भारतीय अदालत के गिरफ्तारी वारंट, इंटरपोल की रेड कार्नर नोटिस के सहारे भारतीय एजेंसियां उसे भारत का नागरिक साबित करने में सफल रही। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सारे सबूतों को देखने के बाद ओमान ने उसके प्रत्यर्पण का फैसला किया। सौरभ चंद्राकर के साथ 2019 में महादेव सट्टा एप शुरू करने वाला सह-प्रमोटर रवि उप्पल फिलहाल दुबई में है और उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। रवि उप्पल के साथ ही चंद्राकर का सहयोगी अनिल अग्रवाल उर्फ अतुल अग्रवाल और पूरे कारोबार का वित्तीय लेन-देन संभालने वाले शुभम सोनी भी दुबई में है और उसके भी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सुभम सोनी ने 2023 में एक ईमेल भेजकर महादेव सट्टा एप चलाने के लिए अधिकारियों और राजनीतिज्ञों को करोड़ों रुपये की संरक्षण मनी देने का दावा किया था। उसी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपये महादेव सट्टा एप के प्रमोटरों द्वारा दिये जाने का खुलासा किया था, जिसकी जांच अभी तक जारी है। 2023 में रायपुर में 5.39 करोड़ रुपये नकद के साथ गिरफ्तार असीम दास ने भी अपने बयान में सुभम सोनी के निर्देश पर भूपेश बघेल तक पहुंचाने की बात कही थी। इस मामले में कई अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है।



छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की नई गाइडलाइन जारी

शहर सत्ता/रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर राज्य शासन ने नीति निर्धारित कर दी है। इस बार किसानों से 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक ही धान खरीदा जाएगा। यानी पिछले वर्षों की तुलना में खरीदी की अवधि 15 दिन कम कर दी गई है। पहले 31 जनवरी तक खरीदी होती थी। वहीं, इस वर्ष भी प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी की सीमा तय की गई है, जिसमें लिकिंग सहित खरीदी शामिल है। धान उपार्जन की जिम्मेदारी मार्कफेड को सौंपी गई है। इधर, खरीदी की तैयारियों के बीच पटवारियों की हड़ताल ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। गिरदावरी और अन्य राजस्व कार्य प्रभावित होने से पंजीयन में परेशानी आ रही है। 31 अक्टूबर पंजीयन की अंतिम तिथि निर्धारित थी, लेकिन बड़ी संख्या में किसानों का पंजीयन और अप्रूवल अटका हुआ है। एग्रीस्टेक में ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पटवारी आईडी से अप्रूवल जरूरी है। इसके बाद ही संबंधित किसानों की जानकारी सोसायटी आईडी में प्रदर्शित होगी और खसरा व रकबे के आधार पर टोकन जारी हो सकेगा। ऐसे में पंजीयन की तिथि बढ़ाने की मांग भी तेज होने लगी है। वर्तमान में फसल विवरण शून्य बताया जा रहा, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में बहुत सारे किसान धान बेचने से वंचित हो जाएंगे। राजनांदगांव जिले में पहले 74 समितियों के अंतर्गत 96 धान उपार्जन केंद्र संचालित थे। इस वर्ष करीब 24 नए केंद्र बढने से इनकी संख्या 120 तक पहुंच जाएगी।

'अर्नब' के बाद अब 'मुरासु' का खतरा, छत्तीसगढ़ में 4 नवंबर तक भारी बारिश की चेतावनी



शहर सत्ता/रायपुर। दीपावली के त्योहार और राज्योत्सव की खुशियों के बीच मौसम ने प्रदेशवासियों और किसानों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के असर से प्रदेश अभी पूरी तरह उबरा भी नहीं था कि बंगाल की खाड़ी में एक और नए तूफान की आहट शुरू हो गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में 2 नवंबर से एक नया चक्रवाती सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिसके सोमवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने की संभावना है।

चक्रवात के नामकरण की कड़ी में इसका नाम मुरासु होना है। इस नए सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के मौसम में फिर तीखा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार, 2 नवंबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछेक स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद, 3 और 4 नवंबर को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश होने का अनुमान है। इस मौसम प्रणाली को देखते हुए प्रशासन ने संबंधित जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी संभावित आपदा से निपटा जा सके।

तीन नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा तूफान

चक्रवाती तूफान के 3 नवंबर 2026 की सुबह दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, यह तूफानी सिस्टम फिलहाल चेन्नई से करीब 630 किलोमीटर और विशाखापत्तनम, नेल्लोर व मछलीपट्टनम से लगभग 710 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अलावा ओंगोल से इसकी दूरी करीब 750 किलोमीटर है। मौसम प्रणाली के तेजी से मजबूत होकर चक्रवाती तूफान और फिर 2 नवंबर तक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर प्रचंड चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है।

3,560 पदों पर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख बदली



शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की प्रस्तावित तारीखों में बदलाव किया है। पहले अक्टूबर 2026 में आयोजित होने वाली ये परीक्षाएं अब दिसंबर में होंगी। प्रशासनिक कारणों से परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। नई तारीखों के अनुसार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 6 दिसंबर और शिक्षक भर्ती परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले 11 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसका आयोजन 6 दिसंबर को किया जाएगा। वहीं, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख भी बदल दी गई है। पहले यह परीक्षा 25 अक्टूबर को होनी थी, जिसे अब 20 दिसंबर 2026 के लिए निर्धारित किया गया है।

16 जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र

परीक्षाओं के आयोजन के लिए प्रदेश के 16 जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने की तैयारी है। इसका उद्देश्य प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रशासन की ओर से परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग में अलग-अलग श्रेणियों के कुल 3,560 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी।

इसमें शिक्षक के 1,068 पद, सहायक शिक्षक के 2,292 पद और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 200 पद शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। परीक्षा की तारीखों में बदलाव के बाद अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

नगर निगमों और निकायों के ऑडिट पर नए निर्देश

CA फर्मों से हर महीने लेनी होगी रिपोर्ट



शररसत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों की आंतरिक ऑडिट व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए राज्य शासन ने नए निर्देश जारी किए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने ऑडिट कार्यों की नियमित समीक्षा और चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) फर्मों से मासिक रिपोर्ट लेना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही, अनुबंध की शर्तों के अनुसार ऑडिट कार्य संतोषजनक पाए जाने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस व्यवस्था की जिम्मेदारी संभागीय संयुक्त संचालकों को सौंपी गई है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका आंतरिक अंकेक्षण (मानक प्रक्रिया) नियम, 2017 के तहत अतिरिक्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, नगरीय निकायों में आंतरिक ऑडिट के लिए चयनित सीए फर्मों के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक अनुबंध करेंगे। इसके बाद ही फर्म को ऑडिट कार्य के लिए कार्यादेश जारी किया जाएगा। शासन ने संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देश दिया है कि वे ऑडिट करने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों से अनुबंध में तय प्रारूप के अनुसार मासिक प्रतिवेदन प्राप्त करें। इससे ऑडिट कार्यों की नियमित निगरानी की जा सकेगी और फर्मों द्वारा किए जा रहे काम की प्रगति का आकलन भी होगा।

कार्य संतुष्टि प्रमाणपत्र के बाद ही होगा भुगतान

आदेश में निविदा की कंडिका 5.4 और 6 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। संभागीय संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालयों को निविदा और अनुबंध की शर्तों के अनुरूप ऑडिट कार्यों की समीक्षा कर भुगतान की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके तहत संबंधित सीए फर्म को कार्य संतुष्टि प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इसके बाद ही भुगतान के लिए आवश्यक राशि की मांग राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) से की जाएगी। यानी ऑडिट का काम संतोषजनक पाए जाने और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही भुगतान किया जा सकेगा।

तत्काल प्रभाव से लागू होंगे निर्देश

राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि नए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आदेश की प्रतिलिपि नगरीय प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, संचालक नगरीय प्रशासन, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सभी जिला कलेक्टरों और संभागीय संयुक्त संचालकों को भेजी गई है। इसके अलावा नगर निगमों के महापौर और आयुक्तों तथा नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई है।

आखिर किसके दबाव में रुकी तहसीलदारों की रवानगी?

शररसत्ता/रायपुर। राजस्व विभाग में तबादला आदेशों की अनदेखी की जा रही है। पटवारियों के बाद अब तहसीलदारों के तबादले भी सवालों के घेरे में हैं। हड़ताल के बाद राजस्व विभाग ने बड़े पैमाने पर तबादले किए, लेकिन कई अधिकारी नई पदस्थापना पर जाने के बजाए पुराने स्थानों पर ही जमे हुए हैं। खासकर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ जैसे बड़े जिलों से बलरामपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और जशपुर जैसे दूरस्थ एवं अनुसूचित क्षेत्रों में जाने वाले तहसीलदारों के मामले में आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा है। वहीं 57 में 19 लोग नई जगहों पर ज्वाइनिंग दे चुके हैं।



बता दें कि राजस्व विभाग ने 9 सितंबर को तहसीलदारों के स्थानांतरण आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद कई अधिकारियों की रवानगी अब तक नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि कुछ तहसीलदार कामकाज का हवाला देकर अपनी रिलीविंग रुकवाने में सफल रहे हैं। वहीं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ जैसे बड़े जिलों में स्थानांतरित किए गए अधिकारी आदेश के अनुरूप तत्काल नई पदस्थापना पर पहुंच गए और कार्यभार भी संभाल लिया। इसके उलट, अनुसूचित एवं दूरस्थ जिलों में पदस्थापना पाने वाले अधिकारियों के मामले में आदेशों का पालन अटका हुआ है।

क्रीम जिलों से मोह, दूरस्थ क्षेत्रों से परहेज

राजस्व विभाग में चर्चा है कि अधिकारी बड़े और सुविधाजनक जिलों में पदस्थ रहना चाहते हैं, जबकि दूरस्थ एवं अनुसूचित क्षेत्रों में जाने से बच रहे हैं। बलरामपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और जशपुर जैसे जिलों में पदस्थापना के आदेश के बावजूद अधिकारियों का नहीं पहुंचना प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चुनौती बनता जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 दिनों के भीतर एकतरफा भारमुक्ति की कार्रवाई की जानी चाहिए।

संपादकीय



सुकांत राजपूत

मॉक पार्लियामेंट या राजनीतिक तमाशा

आम तौर पर प्रतीकात्मक संसद का आयोजन छात्रों को संसदीय कार्यवाही के तौर-तरीकों से परिचित कराने के लिए किया जाता है, लेकिन गत दिवस कांग्रेस की पहल पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर पर विपक्षी दलों की ओर से जो दिखावटी संसद चलाई गई, उसे एक भोंडे राजनीतिक तमाशे के अतिरिक्त और कुछ कहना कठिन है। इस आयोजन ने केवल संसद की गरिमा गिराने का ही काम नहीं किया, बल्कि इसने विपक्ष की फजीहत भी कराई। इसलिए कराई, क्योंकि इस दिखावटी संसद में एक तो सिविल सोसायटी के नाम पर आंदोलनजीवी किस्म के लोगों को भी स्थान दिया गया और दूसरे वोट चोरी के जुमले की आड़ में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन महाभियोग भी लाया गया। इस दौरान न तो उनका और न ही चुनाव आयोग का पक्ष रखने की प्रतीकात्मक ही सही, सुविधा दी गई।

एक तरह से जन महाभियोग लाने वालों ने कंगारू कोर्ट जैसा काम किया और जैसा चाहते थे, वैसा फैसला सुना दिया यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को दोषी करार दिया। यह सब नौटंकी तब हुई, जब मतदाता सूचियों के शुद्धीकरण यानी एसआईआर के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इनमें से कई याचिकाएं विपक्षी नेताओं की हैं। इनमें एक याचिका राहुल गांधी की भी है।

यह याचिका दायर करने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। यदि उन्हें वास्तव में सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है तो फिर दिखावटी संसद बुलाने और दुराग्रह से प्रेरित होकर तथाकथित जन महाभियोग लाने का क्या औचित्य?इस सबसे तो यही सिद्ध होता है कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। जिस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही हो, उस पर बाहर जनसुनवाई करना लोकतांत्रिक मर्यादा और संवैधानिक मूल्यों के ही खिलाफ है।

क्या यह विचित्र नहीं कि राहुल गांधी संविधान की प्रति लिए तो घूमते रहते हैं, लेकिन उसकी भावना के अनुरूप आचरण करने के लिए तैयार नहीं। उन्हें इतनी समझ होनी ही चाहिए कि निराधार आरोपों के सहारे लोगों को गुमराह करने की एक सीमा होती है। अब वह जमाना नहीं रहा कि किसी झूठ को सौ बार दोहराया जाए तो उसे सच साबित किया जा सके।

इससे इनकार नहीं कि एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां हैं और उनके कारण लोगों को परेशानी भी हो रही है, लेकिन इस सबको वोट चोरी कहना तिल को ताड़ बनाना ही है। यदि राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के पास मुख्य चुनाव आयुक्त की कथित धांधलियों के खिलाफ कोई प्रमाण हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। किसी भी मामले में विपक्ष वकील और जज, दोनों की भूमिका एक साथ नहीं निभा सकता।

हॉकी की नई उड़ान, छत्तीसगढ़ की नई पहचान

डॉक्टर कमलेश गोगिया

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के गौरवशाली 26 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इन ढाई दशकों में प्रदेश ने अनेक क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। खेलों के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ ने समय-समय पर नए प्रयोग किए हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय खेल हॉकी को नई पहचान और ऊर्जा देने की दिशा में शुरू हुई छत्तीसगढ़ हॉकी लीग एक अभिनव और दूरगामी पहल के रूप में सामने आई है। राजधानी रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित भारत की पहली छत्तीसगढ़ हॉकी लीग ने प्रदेश की खेल यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। हॉकी इंडिया से मान्यता प्राप्त इस लीग का आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने किया।

छत्तीसगढ़ के खेल इतिहास में 1 नवंबर 2026 की तारीख नई शुरुआत और उम्मीदों के प्रतीक के रूप में याद की जाएगी। इसी दिन लीग के प्रथम संस्करण का फाइनल मुकाबला मैनपाट टाइटन्स और संस्कारधानी स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया। यह अवसर इसलिए भी खास रहा कि राज्य स्थापना दिवस का उत्सव इस बार प्रदेश की विकास यात्रा और सांस्कृतिक वैभव के साथ हॉकी के भविष्य को संवारने के संकल्प से भी जुड़ा। यह पहल दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ खेल प्रतिभाओं को पहचानने, उन्हें अवसर देने और खेल संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

लीग का शुभारंभ केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री डॉ. रक्षा निखिल खड़से तथा उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने किया, जबकि समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। लीग का लोगो छत्तीसगढ़ के मानचित्र पर आधारित रखा गया, जो प्रदेश की भौगोलिक पहचान के साथ विकास और भारतीयता की भावना को अभिव्यक्त करता है। वहीं, इसकी टैगलाइन 'चलव रे संगी, हॉकी खेलबो' ने छत्तीसगढ़ी माटी की आत्मीयता और सामूहिक सहभागिता का संदेश दिया। इसका अर्थ है—आइए दोस्त, मिलकर हॉकी खेलें। इस छोटे-से उद्घोष में खेल को प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ाकर जनभागीदारी का उत्सव बनाने की सोच समाहित है।

आयोजन का आधिकारिक शुभंकर 'बघवा' भी छत्तीसगढ़ की पहचान का सशक्त प्रतीक रहा। बाघ को शुभंकर के रूप में चुनना प्रदेश की समृद्ध वन्यजीव विरासत, प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक गौरव को सम्मान देने जैसा है। इसके माध्यम से साहस, शक्ति, आत्मविश्वास और निडरता जैसे गुणों को खेल भावना से जोड़ा गया।

प्रतियोगिता में छह टीमों—राजधानी रॉयल्स, चित्रकूट चैलेंजर्स, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स, चक्रधर चैंपियंस, न्यायधानी नाइट्स और मैनपाट टाइटन्स ने भाग लिया। इन टीमों के नाम प्रदेश के अलग-अलग अंचलों की भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं को सामने लाते हैं। इस तरह लीग ने खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मंच देने के साथ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को हॉकी के साझा सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया। हालांकि, आयोजन में दर्शकों की अपेक्षित उपस्थिति और व्यापक जनभागीदारी का अभाव कुछ हद तक महसूस हुआ। लेकिन नई पहल के शुरुआती दौर की इन चुनौतियों को उसकी संभावनाओं पर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि इन्हें भविष्य के बेहतर आयोजनों के लिए सीख के रूप में लेना चाहिए।

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इसने प्रदेश में हॉकी को फिर से चर्चा और आकर्षण के केंद्र में लाने का अवसर दिया है। स्थानीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने, नई प्रतिभाओं को सामने लाने और युवा पीढ़ी को हॉकी से जोड़ने की दिशा में यह सकारात्मक कदम है। अब जरूरत है कि इस पहल को एक आयोजन तक सीमित न रखते हुए निरंतरता और व्यापकता प्रदान की जाए। लीग का नियमित आयोजन हो, अधिक टीमों और खिलाड़ियों को अवसर मिले तथा जिला और ग्रामीण स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान कर स्कूलों एवं महाविद्यालयों को भी इससे जोड़ा जाए। साथ ही, दर्शकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार और स्थानीय समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। खेल आयोजन तभी जनआंदोलन का रूप ले सकता है, जब मैदान में खिलाड़ियों के साथ दर्शकों का उत्साह भी दिखाई दे।

छत्तीसगढ़ की धरती में हॉकी प्रतिभाओं को जन्म देने और निखारने की अपार संभावनाएं हैं। आवश्यकता है उन्हें उचित मंच, संसाधन, बेहतर प्रशिक्षण और निरंतर प्रोत्साहन देने की। छत्तीसगढ़ हॉकी लीग ऐसा मंच बन सकती है, जहां से निकलने वाले खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करें। इसके लिए लीग को दीर्घकालिक खेल विकास योजना से जोड़कर प्रदेश की स्थायी खेल परंपरा का हिस्सा बनाना होगा।

उम्मीद है कि 'चलव रे संगी, हॉकी खेलबो' का उद्घोष केवल स्टेडियम की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांवों की पगडंडियों से लेकर शहरों के मैदानों तक गूंजेगा। आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ के बच्चे हॉकी की स्टिक थामकर नए सपने बुनेंगे और प्रदेश की माटी से निकले हॉकी के सितारे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी चमक बिखेरेंगे।

छत्तीसगढ़ की हॉकी विरासत : ओलंपिक गौरव से नई पीढ़ी के सपनों तक

छत्तीसगढ़ की धरती का हॉकी से रिश्ता बेहद पुराना, आत्मीय और गौरवशाली रहा है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृतियों से जुड़ी इस धरती ने भारतीय हॉकी को ऐसी अनेक प्रतिभाएं दी हैं, जिन्होंने अपने खेल कौशल और उपलब्धियों से राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी प्रदेश का मान



बढ़ाया है। अविभाजित मध्यप्रदेश के दौर से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद तक यहां की हॉकी परंपरा निरंतर समृद्ध होती रही है। ओलंपियन लेस्ली वाल्टर क्लॉडियस और एरमेन आर. बेस्टियन जैसे महान खिलाड़ियों से लेकर विन्सेंट लकड़ा, नीता डुमरे, सबा अंजुम और मृणाल चौबे जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों तक, इस धरती ने भारतीय हॉकी को अनेक अनमोल सितारे दिए हैं। इसी गौरवशाली परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं रेणुका यादव, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की पहली महिला ओलंपियन बनने का गौरव हासिल कर प्रदेश की बेटियों के सामने सपनों को साकार करने की एक नई मिसाल पेश की। यह गौरवशाली विरासत इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की माटी में हॉकी प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं रही। यहां जरूरत हमेशा इन प्रतिभाओं को सही अवसर, बेहतर प्रशिक्षण, पर्याप्त संसाधन और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की रही है।

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के प्रमुख तथ्य एवं उपलब्धियां

- रायपुर में उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की छह फ्रेंचाइजी और उनकी टीमों का ऐलान किया।
- ड्रॉ के माध्यम से फ्रेंचाइजी को टीमों का आवंटन किया गया और सभी टीमों की जर्सी भी लॉन्च की गई।
- 1. चक्रधर चैंपियंस – जिंदल स्टील लिमिटेड
- 2. न्यायधानी नाइट्स – साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL)
- 3. राजधानी रॉयल्स – श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड
- 4. मैनपाट टाइटन्स – छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल
- 5. संस्कारधानी स्ट्राइकर्स – सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड
- 6. बैलाडीला बुल्स – एनएमडीसी लिमिटेड
- ड्रॉ के जरिए प्रत्येक फ्रेंचाइजी को 22 खिलाड़ियों का दल और एक मुख्य कोच आवंटित किया गया।
- भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी एवं पूर्व कप्तान सरदार सिंह को छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का एंबेसडर बनाया गया।
- लीग में छह टीमों के कुल 132 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें छत्तीसगढ़ के 108 स्थानीय और 24 अतिथि खिलाड़ी शामिल रहे।
- हर टीम में 22 खिलाड़ी शामिल रहे, जिनमें चार अतिथि खिलाड़ी और एक पूर्व ओलंपियन मार्की खिलाड़ी भी शामिल था।
- 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक आयोजित लीग में 18 पुरुष हॉकी मुकाबले खेले गए। इसके अतिरिक्त एक प्रदर्शनी महिला हॉकी मैच भी आयोजित हुआ।
- खिलाड़ियों और टीमों के लिए कुल 21 लाख रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई थी।
- विजेता टीम को 11 लाख रुपये और उपविजेता टीम को छह लाख रुपये प्रदान किए गए।
- सभी 18 मुकाबलों में प्रत्येक मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को 10 हजार रुपये दिए गए।
- प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया।
- सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी (टॉप स्कोरर), सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी खिलाड़ी और अंडर-21 वर्ग के उभरते खिलाड़ी को 30-30 हजार रुपये के पुरस्कार दिए गए।
- लीग के मुकाबलों का सीधा प्रसारण जियोहॉटस्टार पर किया गया, जिससे देशभर के हॉकी प्रेमियों को प्रतियोगिता से जुड़ने का अवसर मिला।

असहनीय हो चुकी है न्याय में देरी

इस कथन से शायद ही कोई अपरिचित हो कि "न्याय में देरी न्याय से वंचित करना है, लेकिन बार-बार की देरी तो अन्याय है।" महान संवैधानिक विशेषज्ञ एवं न्यायविद् नानी पालकीवाला का यह कथन भी खूब प्रचलित है कि भारत में न्याय प्रशासन की सबसे बड़ी खामी देरी है और मैं दुनिया के किसी भी ऐसे देश से अवगत नहीं जहां मुकदमे इतने लंबे समय तक चलते हों, जितने भारत में। उनका यह भी कहना था, भारत में कानून बहुत ज्यादा हैं और न्याय बहुत कम। ये सभी चर्चित कथन भारतीय न्यायपालिका के समक्ष खड़ी चुनौतियों की गंभीरता को ही बयान करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल में नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी और नेशनल कंपनी ला अपीलेट ट्रिब्यूनल अर्थात एनसीएलएटी की प्रशासनिक स्वतंत्रता पर गंभीर चिंता जताते हुए यह टिप्पणी करना कि इन संस्थाओं को कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 'पूरी तरह हाईजैक' कर लिया है, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि केवल विशेष ट्रिब्यूनल या न्याय मंच बना देने भर से त्वरित न्याय सुनिश्चित नहीं हो जाता। इन संस्थाओं में भारी रिक्तियों, बुनियादी ढांचे के अभाव और प्रशासनिक नियंत्रण में ढिलाई के कारण मुकदमों का निपटारा हफ्तों या महीनों में होने के बजाय सालों-साल खिंच जाता है, जिससे व्यावसायिक विवादों और आम नागरिकों को भारी आर्थिक और मानसिक क्षति होती है। यह विडंबना ही है कि जिन विशेष संस्थाओं का गठन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए किया गया था, वे स्वयं प्रशासनिक और व्यवस्थागत जकड़न का शिकार हैं।

निचली अदालतों, अपीलीय ट्रिब्यूनलों और न्याय के अन्य मंचों पर मुकदमों के निस्तारण में लंबी देरी और कई बार आने वाले अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण फैसलों का एक सबसे बड़ा कारण जवाबदेही का पूर्ण अभाव है। अक्सर निचली अदालतों द्वारा पारित सतही या कानूनी रूप से कमजोर निर्णयों को उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है और उन पर कड़ी टिप्पणियां भी की जाती हैं, परंतु यह बात कभी सार्वजनिक नहीं होती कि ऐसे न्यायाधीशों के खिलाफ अंततः क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई? इसके विपरीत इन न्यायाधीशों की पदोन्नति का आधार और आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली पूरी तरह से अपारदर्शी है, जिससे आम जनता और विशेष रूप से वादियों के मन में न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है।

इस दोहरी चुनौती से पार पाने के लिए यह समझना आवश्यक है कि व्यवस्था की कमजोरी केवल प्रशासनिक या बुनियादी ढांचे के अभाव तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक अनुशासन की कमी भी है। एक तरफ जहां कार्यपालिका के लिए यह आवश्यक है कि वह न्यायिक संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन और स्टाफ देकर उनकी गति को बाधित करने वाले कारणों का निवारण करे, वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका के भीतर भी न्यायाधीशों की जिम्मेदारी बनती है कि वे उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए बिना अनावश्यक विलंब के त्वरित निर्णय दें। केवल बुनियादी ढांचे की कमी को ही देरी का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि न्यायाधीशों के पास अपनी कार्यशैली और समय-प्रबंधन में सुधार करके स्थिति को काफी हद तक बेहतर बनाने की शक्ति होती है। इसका उन्हें उपयोग करना ही चाहिए।

न्याय में देरी की विकट समस्या से निपटने के लिए केवल निचली अदालतों ही नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय सहित संपूर्ण न्याय तंत्र की जवाबदेही तय करना अनिवार्य हो गया है, ताकि लोगों को समय पर सही न्याय मिल सके। प्रख्यात न्यायविदों और न्यायिक सुधारों पर बल देने वालों का यह स्पष्ट मत रहा है कि जब तक न्यायपालिका अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली में आधुनिक प्रबंधन और कड़े अनुशासन



को नहीं अपनाती, तब तक केवल नए-नए कानून बना देने से स्थिति नहीं सुधरेगी। इस दिशा में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के साथ विधि आयोगों ने बार-बार इस पर बल दिया है कि मुकदमों की सुनवाई के दौरान तारीख पर तारीख की संस्कृति पर कड़ाई से रोक लगनी चाहिए और अनावश्यक रूप से मामले को लटकाने वाले वकीलों या पक्षों पर भारी वित्तीय दंड लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उच्चतर न्यायपालिका से लेकर अधीनस्थ अदालतों तक हर स्तर पर यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि बहस पूरी होने के बाद एक निश्चित समयसीमा के भीतर पारदर्शी निर्णय दिए जाएं। इस तय सीमा का पालन न होने पर संबंधित पीठासीन अधिकारी की कड़ाई से वार्षिक समीक्षा हो।

मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए पूर्व न्यायविदों द्वारा 'केस मैनेजमेंट कांफ्रेंस' की जो वकालत की गई है, उसे जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। इस व्यवस्था के तहत न्यायाधीश दोनों पक्षों के वकीलों के साथ बैठकर शुरुआत में ही विवाद के मुख्य बिंदुओं को तय करते हैं, जिससे सुनवाई के दौरान अनावश्यक और लंबी बहसों से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त चूंकि खुद सरकार देश के कुल मुकदमों के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार है, अतः उन पर भी लगाम लगनी चाहिए। इसके लिए विभिन्न कानूनी समितियों ने लगातार यह सिफारिश की है कि सरकारी विभागों को हर मामले में विपरीत निर्णय के बाद आंख मूंदकर अपील करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए आंतरिक जांच समितियां बनाकर अक्षम अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करना आवश्यक है, ताकि वे लोगों, सरकारी संसाधनों और साथ ही अदालतों का समय बर्बाद करने से बचें।

भारतीय न्याय प्रणाली का कायापलट केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की एक अनिवार्य शर्त है। जब तक अदालतों की पारदर्शी तरीके से कार्यकुशलता और न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती, तब तक करोड़ों लंबित मामलों के बोझ तले दबी न्याय व्यवस्था आम आदमी के लिए सुलभ और भरोसेमंद नहीं बन पाएगी। न्याय मिलने में देरी का सिलसिला देश के विकास के लिए अब असहनीय हो चुका है। यह सिलसिला देश के विकास को बाधित करने के साथ मुकदमों में फंसे करोड़ों लोगों के समय और संसाधन की बर्बादी का कारण बनने के साथ ही उन्हें निराश भी कर रहा है।



बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए 1 नवंबर को बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर बताया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के शहर बेंगलुरु से बेहतर रेल कनेक्टिविटी की दिशा में एक और कदम. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बेंगलुरु और मुंबई के बीच कनेक्टिविटी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी. इस ट्रेन की शुरुआत से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों राज्यों को सीधा फायदा होगा. खासतौर पर युवाओं, आईटी प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए यह यात्रा बहुत आसान, आरामदायक और सुविधाजनक साबित होगी.' इससे पहले रेल मंत्रालय ने एक्स पोस्ट में बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रेलवे ने कहा कि यह सेवा लंबी दूरी की रेल यात्रा में यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर अनुभव प्रदान करेगी.

29वें वायुसेना प्रमुख बने एयर चीफ मार्शल आशुतोष

नई दिल्ली। देश के 29वें वायुसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने वाले एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने अपनी प्राथमिकताओं का स्पष्ट खाका खींच दिया है। उन्होंने रविवार को कहा कि वायुसेना की स्वीकृत फाइटर स्क्वाड्रन क्षमता को बहाल करना, तेजस और एडवांस्ड मीडियम काम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) जैसे स्वदेशी कार्यक्रमों में तेजी लाना और तीनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल को मजबूत करना उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। आसमान में अपनी ताकत को धार देने के लिए उन्होंने 'वायु' नाम से चार सूत्रीय विजन पेश किया है। इसके तहत सतर्कता और अभियानगत तैयारी, आत्मनिर्भरता, सामरिक नवाचार और तीनों सेनाओं में तालमेल पर विशेष जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि हर स्क्वाड्रन, हर रडार, हर एयर डिफेंस यूनिट और साथ ही वायुसेना के हर एक योद्धा (एयर वॉरियर) को किसी भी पल कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। साढ़े तीन हजार से अधिक घंटों की उड़ान का अनुभव रखने वाले एक कुशल फाइटर पायलट एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने स्पष्ट किया कि तेजस (एलसीए एमके 1ए और एमके 2) तथा एएमसीए कार्यक्रम के विकास को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है ताकि ऑपरेशनल मांगों को पूरा किया जा सके।

चक्रवात 'मुरासु' आंध्र प्रदेश की तरफ तेजी से बढ़ रहा

नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात 'मुरासु' (Cyclone Murasu) और अधिक शक्तिशाली हो गया है और आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है। भारी बारिश और तेज हवाओं के पूर्वानुमान को देखते हुए, ओडिशा ने अपने दक्षिणी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। भारतीय मौसम विभाग IMD) ने आंध्र प्रदेश और उससे सटे उत्तरी तमिलनाडु के तटों के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी किया है। इस तूफान के और अधिक शक्तिशाली होकर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है।इसके 2 नवंबर की देर रात से 3 नवंबर की सुबह के बीच नेल्लोर और नरसापुर के बीच दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट के पार करने की उम्मीद है। रविवार सुबह 11.30 बजे जारी अपने ताजा बुलेटिन में, IMD ने बताया कि यह चक्रवाती तूफान 23 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है।

अवैध था 2024 का लोकसभा चुनाव

रामलीला ग्राउंड से राहुल गांधी का बड़ा आरोप, 15% मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए



नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को INDIA गठबंधन के नेताओं महारैली की। इस रैली का नारा 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रखा गया। इस रैली में विपक्षी दलों के नेता, पार्टी कार्यकर्ता, छात्र संगठन और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। रैली के जरिए विपक्ष की ओर से चुनावी अनियमितताओं का मुद्दा उठाने, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का विरोध करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई। INDIA गठबंधन के बड़े नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर से खुली बसों में सवार होकर रामलीला मैदान पहुंचे। इस रैली में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव समेत 19 विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल हुए। सभी विपक्षी नेताओं ने एक सुर में वोट चोरी के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की।

इस देश में सालों से हो रही वोच चोरी- राहुल गांधी

INDIA गठबंधन की महारैली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "इस देश में सालों से वोटों की चोरी हो रही है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और 2024 के लोकसभा चुनाव, इन सभी चुनावों में वोटों की चोरी हुई है। EVM के जरिए, और वोटर लिस्ट से नाम हटाने या उसमें नाम जोड़ने के जरिए वोट चुराए गए हैं।"INDIA गठबंधन की महारैली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "2024 के चुनावों के बाद भारत के 15 प्रतिशत मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इसका मतलब है कि 2024 का चुनाव एक अवैध चुनाव था। यह एक चुराया गया चुनाव था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि चुनाव आयोग ऐसा कह रहा है।"

प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता से जाने पर ही बचेगा लोकतंत्र-खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और महाराष्ट्र, बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों को 'चोरी की सरकार' करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता से जाने पर ही लोकतंत्र बच सकेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में 'इंडिया' गठबंधन की 'वोट चोरी' के खिलाफ आयोजित रैली को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश की जाती है, लेकिन कांग्रेस और गठबंधन के नेता इससे डरने वाले नहीं हैं।



कपिल सिब्बल का BJP पर निशाना, कहा- 'ये अंत की शुरुआत'

रामलीला मैदान में 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की रैली में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस मार्च को "केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार के 'अंत की शुरुआत' बताया." कांग्रेस के नेताओं ने इस मार्च के दौरान SIR और CEC के मुद्दे पर ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार की जमकर आलोचना की. कपिल सिब्बल ने रामलीला मैदान में आयोजित रैली में कहा कि "हम 2016 के बाद के उनके भ्रष्टाचार का इतिहास बताएंगे. सरकार ने ही अराजकता पैदा की है, अगर उन्होंने संविधान के अनुसार काम किया होता, तो यह नौबत नहीं आती." CEC ज्ञानेश कुमार को उन्होंने महज एक 'प्यादा' बताया.हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की. सुक्खू ने कहा, "ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए." कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि रैली में लोगों की भारी भीड़ यह दिखाती है कि इसमें पूरे देश के लोग शामिल हुए हैं.

'राहुल गांधी की रैली सुपर फ्लॉप', BJP ने किया पलटवार



भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने रविवार (1 नवंबर, 2026) को दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही इंडिया ब्लॉक की महारैली को सुपर फ्लॉप रैली करार दिया है. इसके साथ ही, BJP ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है.BJP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडिया ब्लॉक की महारैली के दौरान रामलीला मैदान का एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसा और की रैली को फ्लॉप बताया.भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने X प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए वीडियो पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'राहुल गांधी रैली में मंच से बोल रहे हैं और मैदान में कुर्सियां खाली पड़ी हैं. कांग्रेस पार्टी 50 हजार लोगों की क्षमता वाले रामलीला मैदान को भी पूरी तरह से भर नहीं पाई. यह पूरी तरह से एक फ्लॉप रैली है.' वहीं, एक अन्य X पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, 'राहुल गांधी का एक और लॉन्च मिशन फेल हो गया है.'

BJP ने राहुल गांधी की रैली को देश को अराजकता की आग में झोंकने की कोशिश बताया है. पार्टी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, 'रामलीला मैदान में राहुल गांधी की रैली देश को अराजकता की आग में झोंकने और चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है. इसके पीछे मकसद साफ है- सिखों के जख्मों का अपमान करना. त्योहारों में व्यापारियों के कारोबार पर चोट करना. चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना और विदेशी इशारों पर भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना.'भाजपा ने कहा, 'राहुल गांधी कान खोलकर सुन लो, अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश की शांति, संप्रभुता और सुरक्षा से खिलवाड़ 140 करोड़ भारतीय बर्दाश्त नहीं करेंगे!'

मॉक पार्लियामेंट ही पीएम बन सकते हैं राहुलः अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के आह्वान पर आयोजित रामलीला मैदान की रैली और मॉक पार्लियामेंट को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, 'मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि आपको अगर प्रधानमंत्री बनना है तो ऐसे ही मॉक पार्लियामेंट करते रहिए. आपका नंबर नहीं लगने वाला है.' अमित शाह ने पंजाब में NDA की सरकार बनाने की बात दोहराई. उन्होंने कहा, 'पंजाब में चुनाव आने वाला है वहां पर भी NDA सरकार बनानी है. 1 नवंबर 1984 को सिख विरोधी दंगे हुए जिनमें हजारों सिखों को मार दिया गया. राजीव गांधी ने दंगों को लेकर कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है. ऐसा कांग्रेस के नेताओं के अलावा कोई कर नहीं सकता. हमने दंगा करने वालों के केस दोबारा खुलवाये और कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाला. भारत ने ऐसे राज्य प्रेरित दंगे न कभी देखे थे और न कहीं देखेंगे।

रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए बातचीत कर रहा भारत?

नई दिल्ली। अमेरिका के अटलांटा में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है. इस दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में रूस-यूक्रेन युद्ध के संबंध में बयान दिया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दिल्ली में और उससे पहले बिश्केक में राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत की थी. मैं पहले मॉस्को गया था और आज भी मैंने लावरोव के साथ इस पर चर्चा की. एस. जयशंकर ने ANI को दिए एक इंटरव्यू में आगे कहा कि इस बीच मैं कीव भी गया था और हम यूक्रेनी पक्ष के संपर्क में हैं. हम इस मामले में अमेरिकियों के साथ भी तालमेल बिठा रहे हैं, क्योंकि शांति मध्यस्थता को लेकर उनकी अपनी पहल है. इस संबंध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो को मोटे तौर पर पता है कि यहां क्या चल रहा है. इसके आगे डिटेल जानकारी या मौजूदा हालात जैसी बातों को सार्वजनिक रूप से साझा करने की स्थिति में मैं नहीं हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस-यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की बार-बार अपील की है. उन्होंने 31 अगस्त 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई मुलाकात कहा था कि हमें कभी न खत्म होने वाले युद्ध की स्थिति से आगे बढ़कर युद्ध के अंत की ओर बढ़ना होगा।

हम असहाय होकर केवल तमाशा नहीं देख सकते: विदेश मंत्री



नई दिल्ली। इजरायल में गुरुवार को हुए चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है. किसी भी प्रमुख गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं मिला है. इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता के लिए चुनौती बढ़ती दिखाई दे रही है. 'टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के अनुसार, दो प्रमुख अरब पार्टियां रा'म और जॉइंट लिस्ट, जिन्होंने मिलकर 19 सीटें जीती हैं, नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी गठबंधन का समर्थन कर सकती हैं. यह गठबंधन गादी आइजेनकोट के नेतृत्व में है. हालांकि, इन अरब पार्टियों की सरकार में सीधे शामिल होने की इच्छा नहीं है. वे बाहर से समर्थन देकर नई सरकार बनाने में मदद कर सकती हैं.

जॉइंट लिस्ट नेतन्याहू विरोधी पार्टियों को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है. पार्टी खुद सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन मौजूदा सरकार को हटाने के प्रयास में सहयोग करना चाहती है. जॉइंट लिस्ट के वरिष्ठ अरब सांसद अहमद तिबी ने कहा, "हम उन सभी की मदद करना चाहते हैं, जो इस खराब सरकार को गिराकर इसकी जगह दूसरी सरकार लाना चाहते हैं. हम सुधार और उम्मीद का हिस्सा बनना चाहते हैं. " रिपोर्ट में तिबी को जॉइंट लिस्ट का दूसरा प्रमुख उम्मीदवार बताया गया है. वहीं, अरब राजनीतिक आंदोलन से जुड़े अहम व्यक्ति जाफर फराह ने 'द टेलीग्राफ' को बताया कि रा'म और जॉइंट लिस्ट, दोनों इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग को विपक्षी गठबंधन का समर्थन करने की अपनी इच्छा से अवगत करा सकती हैं. फराह के मुताबिक, ये पार्टियां पूर्व इजरायली सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देने की सिफारिश करेंगी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी अरब पार्टी बलाद के तीन सांसद शायद इस सिफारिश का समर्थन न करें, लेकिन बाकी दल ऐसा कर सकते हैं. फराह इजरायल में अरब समुदाय के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक वकालत समूह से जुड़े हैं. वह चुनाव में जॉइंट लिस्ट के उम्मीदवार भी बनने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी. जॉइंट लिस्ट के सांसद अहमद तिबी ने कथित तौर पर गादी आइजेनकोट से कहा कि उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री यित्जाक रबिन की तरह बनना चाहिए. इसके जरिए तिबी ने संकेत दिया कि उनकी पार्टी विपक्षी गठबंधन की सरकार को बाहर से समर्थन दे सकती है।

मुआवजा देने से इनकार किया

ब्रिटेन गुलामी के लिए भारत समेत 56 देशों से माफी पर तैयार

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार स्लेव ट्रेड में ब्रिटेन की ऐतिहासिक भूमिका के लिए माफी मांगने को तैयार है. हालांकि उन्होंने आर्थिक मुआवजे की संभावना को खारिज कर दिया है. बर्नहम ने शुक्रवार 30 अक्टूबर 2026 को द गार्डियन में एक आर्टिकल में लिखा कि वे स्लेव ट्रेड के लिए भारत समेत 56 देशों से माफी मांगने के लिए तैयार है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम का माफी मांगने वाला बयान कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के पहले सामने आया है, जो अगले हफ्ते एंटीगुआ और बारबुडा में होने वाली है. काफी लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि ब्रिटेन को गुलामी के लिए उन देशों से माफी मांगनी चाहिए और मुआवजा देना चाहिए, जिनमें भारत समेत 56 देश शामिल है.

30 लाख अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर भेजा

ब्रिटेन ने लगभग 30 लाख अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर अमेरिका में ब्रिटेन की कॉलोनियों के बागानों में काम करने के लिए भेजा गया था. ब्रिटेन ने 1807 में अपने साम्राज्य में गुलामों के व्यापार को खत्म करना शुरू किया. 1833 में गुलामी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, हालांकि 1838 तक सभी गुलामों को आज़ादी नहीं मिल पाई थी. 1833 में, ब्रिटेन ने गुलामों के मालिकों को कुल 20 मिलियन पाउंड का मुआवजा, जो उस समय सरकार के सालाना बजट का 40 फीसदी था.



प्रधानमंत्री की आलोचना की.

भारत से कितने लोग गए काम करने

गुलामी खत्म होने के बाद, 1838 से 1917 के बीच ब्रिटिश उपनिवेशों में अनुबंधित श्रम की एक व्यवस्था पनपी. भारत से लगभग 20 लाख पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को ब्रिटिश साम्राज्य के तहत कैरेबियन से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक भेजा गया, ताकि वे बागानों में काम कर सकें. इनमें से कई मजदूरों का शोषण किया गया और उन्हें काम की शर्तों के बारे में गुमराह किया गया. कुछ लोगों का अपहरण कर लिया गया और उनकी तस्करी की गई. इनमें से ज्यादातर मजदूर वापस भारत लौटने की स्थिति में नहीं थे.

शशि थरूर का रिएक्शन

बर्नहम के बयान पर शशि थरूर ने रिएक्शन देते हुए कहा कि मैंने लंबे समय से यह तर्क दिया है कि ब्रिटेन चाहे जो भी हर्जाना देने की पेशकश करे, कोई भी रकम न तो उचित होगी और न ही स्वीकार्य. हालांकि, उपनिवेशवाद की तबाही के लिए नैतिक प्रायश्चित बहुत जरूरी है. थरूर ने गुलामी के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगने की बर्नहम की इच्छा का स्वागत किया, लेकिन उपनिवेशवाद के लिए व्यापक माफी न मांगने पर

होर्मुज में 27 भारतीयों वाले टैंकर पर हमला

नई दिल्ली। ग्लोबल ऑयल सप्लाई की रीढ़ माने जाने वाले 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' में समुद्री जंग का खतरनाक खेल फिर से शुरू हो चुका है. अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच 30 अक्टूबर को पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर MT लुईस 1 पर संदिग्ध हमलावरों ने लिम्पेट माइन्स से हमला किया. इस हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में भीषण आग लग गई और वह कुछ देर के लिए ठप हो गया. इस जहाज पर 27 भारतीय नाविक सवार थे. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाकर जहाज को दोबारा रवाना कर दिया गया है. केंद्रीय शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि हमले के कारण जहाज के इंजन रूम में आग लग गई और टैंकर अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गया. राहत की बात ये है कि सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं. सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए पुष्टि की है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में दो जहाजों को निशाना बनाया गया. 29 अक्टूबर को लाइबेरियाई झंडे वाले कच्चे तेल के बड़े टैंकर MT अरजाना पर हमला हुआ, जिसमें 2 भारतीय नागरिक सवार थे. इसके अगले ही दिन 30 अक्टूबर को पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर MT लुईस 1 को निशाना बनाया गया, जिस पर 27 भारतीय नाविक तैनात थे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार दोनों जहाजों की प्रबंधन कंपनियों के लगातार संपर्क में है।



भारत ने कबड्डी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता डबल गोल्ड

लंदन। कबड्डी में भारत को दोहरी सफलता मिली है. कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला, दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीत लिया है. भारत की पुरुष टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 54-20 से बुरी तरह हरा दिया, वहीं महिला टीम ने यूगांडा को 35-15 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया. यह कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप का सबसे पहला संस्करण रहा, जिसके दोनों गोल्ड जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया है. सुरजीत सिंह की कप्तानी वाली मेंस टीम ने पहले हाफ में 15-2 की बढ़त हासिल कर ली थी. पहले 20 मिनट में टीम इंडिया 20 अंकों की विशाल बढ़त बना चुकी थी. श्रीलंका का डिफेंस और रेडिंग डिपार्टमेंट बुरी तरह चरमरा गया था. भारत की पुरुष टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही और कोई उसके सामने कड़ी चुनौती पेश ही नहीं कर पाया.टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा स्कोर आदित्य शिंदे ने किया, जिन्होंने 6 टच पॉइंट्स समेत 10 अंक हासिल किए. उनके अलावा भरत हुड्डा और पंकज मोहिते ने क्रमशः 8 और 6 अंक बटोर कर टीम की जीत में अहम योगदान दिया. भारत के लिए डिफेंस में योगेश दहिया ने कहर बरपाया और कुल 5 टैकल पॉइंट्स अर्जित किए. गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने तिरंगे के साथ लैप ऑफ ऑनर भी किया.

जनवरी में फिर बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का डीए

नई दिल्ली। लेबर ब्यूरो ने अभी हाल ही में सितंबर 2026 के लिए खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं, जिसे 'ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स - इंडस्ट्रियल वर्कर्स' (AICPI-IW) के जरिए ट्रैक किया जाता है. औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) सितंबर में अगस्त के मुकाबले 1.1 अंक बढ़कर 155.5 अंक पर पहुंच चुका है. इस उछाल के चलते मौजूदा DA (महंगाई भत्ता) 65.81% तक पहुंच गया है. अब जनवरी 2027 के लिए DA में बढ़ोतरी की अगली घोषणा जनवरी से दिसंबर 2026 तक की औसत महंगाई दर पर निर्भर करेगी. 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के फॉर्मूले के आधार पर जनवरी 2027 में इसके 68% तक पहुंचने की उम्मीद है. चूंकि जनवरी 2027 का अंतिम डीए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2026 के महंगाई आंकड़ों पर निर्भर करेगा.ऐसे में अगर अगले तीन महीनों में खुदरा महंगाई मौजूदा रफ्तार से बढ़ती है और सूचकांक अक्टूबर में 156.8, नवंबर में 158.1 और दिसंबर में 159.1 तक जाता है, तो 12 महीनों का औसत बढ़कर 151.3 (2001 बेस पर परिवर्तित) हो जाएगा. इस स्थिति में जनवरी 2027 का सटीक डीए 68.56% यानी राउंड फिगर में पूरे 68% तक पहुंच जाएगा.

मिस्टर बिस्ट को हार्दिक ने बेसबॉल में हराया

नई दिल्ली। मिस्टर बीस्ट हाल ही में भारत आए थे, जहां उन्होंने भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ एक बेसबॉल चैलेंज किया. जीतने वाले के लिए एक लाख अमेरिकी डॉलर इनाम था. क्रिकेटर के बेसबॉल शॉट देखकर दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट भी हैरान रह गए, उन्होंने कहा कि कोई नहीं कह सकता कि हार्दिक का ये पहला शॉट था. भारत दौरे पर मिस्टर बीस्ट रणबीर कपूर से भी मिले थे, वह आगरा में ताज महल देखने भी गए थे. हार्दिक पांड्या के साथ उन्होंने बेसबॉल चैलेंज किया, जिसमें उनके और क्रिकेटर के बीच मैच था. बेसबॉल शॉट से गेंद को 3 बार स्टेडियम के बाहर पहुंचाना था।

सीरीज जीतने के बाद भी टीम इंडिया पर उठे सवाल

लगातार दो मैच हारने से नाराज कप्तान



नई दिल्ली। टीम इंडिया ने रविवार (01 नवंबर) को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवां टी20 गंवा दिया. 191 रनों का पीछा करते हुए मेजबान न्यूजीलैंड ने सिर्फ 18 ओवर में जीत दर्ज कर ली. यह भारत के लिए वाकई शर्मनाक हार रही. मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने बताया कि उनकी टीम को कहां मजबूती की जरूरत है. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सीखने को काफी कुछ मिला. अय्यर ने फील्डिंग और गेंदबाजी में सुधार को लेकर बात की. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि शुरुआती तीन मैच जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज जीत ली थी, लेकिन आखिरी दोनों मैचों में न्यूजीलैंड ने शानदार वापसी करते हुए बाजी मारी. सीरीज 3-2 से भारत के नाम रही.

फील्डिंग और गेंदबाजी में बेहतर की जरूरत

पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में अय्यर ने कहा, "हम गेंदबाजी और फील्डिंग में और बेहतर कर सकते थे. हमारी फील्डिंग थोड़ी ढीली रहा लेकिन यह सीखने का शानदार अनुभव था. विदेश में आकर, न्यूजीलैंड में अलग-अलग परिस्थितियों और मैदानों पर खेलने से हमें काफी कुछ सीखने को मिला. यह हमारे लिए सीखने का शानदार मौका रहा."

आखिरी 2 मैचों में किया प्रयोग

अय्यर ने कहा, "शुरुआती तीन मैच ने हमारे लिए लय तय की. इसके बाद आखिरी दो मुकाबलों में मुझे लगा कि हम ऐसी स्थिति में थे जहां हम कुछ प्रयोग करना चाहते थे और खुद को थोड़ी ज्यादा चुनौती देना चाहते थे. आज इसके लिए सही मौका था और जाहिर है कि हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह हमारे लिए सीखने का अच्छा अनुभव रहा."

सुधार की गुंजाइश पर क्या बोले?

अय्यर ने आगे कहा, "मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता क्योंकि हमें अब वनडे मैच खेलने हैं लेकिन खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं. जब आप विदेश दौरे पर जाते हैं तो खेल के अलग-अलग पहलुओं में आपको अलग-अलग मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. जितना ज्यादा आप इन मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं, उतना ही बेहतर होता जाता है."



सोशल मीडिया पर लोगों ने किया गंभीर को ट्रोल

नई दिल्ली। टीम इंडिया ने रविवार (01 नवंबर) को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में हार का सामना किया. मैच में पहले बैटिंग करने के बाद टीम इंडिया ने 20 ओवर में 191/8 रन बनाए. चेज में न्यूजीलैंड ने सिर्फ 18 ओवर में 195/3 रन बनाकर एकतरफा जीत हासिल की. वहीं भारत की हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने एक पोस्ट शेयर करके रिएक्शन दिया. गंभीर ने सिर्फ 3 लाइनों में बड़ी बात कह दी. टीम इंडिया ने शुरुआती लगातार 3 मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा कर लिया था, लेकिन आखिरी 2 मुकाबले मेजबान न्यूजीलैंड ने जीते. इन मैचों में हार के बाद से ही गंभीर की जमकर आलोचना हो रही है. हालांकि मैच से पहले भी हेड कोच ने अपने एक बयान में कहा था कि उनका काम सभी को खुश रखने का नहीं है.

लोगों ने लगा दी क्लास

उनकी इस पोस्ट पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की. एक यूजर ने लिखा, "याद रखिए, यह आपके पिता की टीम नहीं है." एक दूसरे यूजर ने लिखा, "वैभव को खिलाइए. कुछ कड़े फैसले लीजिए. टीम बहुत बार लड़खड़ा रही है." इसी तरह लोगों ने अलग-अलग कमेंट किए.

ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ 341 रन बनाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड



नई दिल्ली। न्यूजीलैंड दौरे पर पांच मैचों की टी20 सीरीज भारतीय टीम ने 3-2 से जीती. शुरुआती तीन मैच भारत ने जीते. इसके बाद चौथे और पांचवें टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया. चौथा टी20 न्यूजीलैंड ने 87 रनों से जीता और पांचवें टी20 में 7 विकेट से बाजी मारी. इस सीरीज में न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने इतिहास रच दिया. ग्लेन फिलिप्स अब द्विपक्षीय टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में ग्लेन फिलिप्स ने 113.67 की औसत और 185.33 के स्ट्राइक रेट से 341 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 29 चौके और 20 छक्के निकले. वह इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने 197 रन बनाए. ग्लेन फिलिप्स एक टी20 द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में कुल 341 रन बनाए. ग्लेन फिलिप्स ने इंग्लैंड के स्टार ओपनर फिल साल्ट को पीछे छोड़ इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है. साल्ट ने साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में 331 रन बनाए थे. हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेले गए पांचवें टी20 में न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से बाजी मारी।

ईशान किशन ने एक कैलेंडर ईयर में बनाए सबसे ज्यादा रन



नई दिल्ली। हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में ईशान किशन ने दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए. सैमसन और अभिषेक के जल्द आउट होने के बाद ईशान किशन ने 32 गेंद में 61 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 2000 रन पूरे किए. साथ ही एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए. पांचवें टी20 में ईशान किशन ने 32 गेंद में 61 रनों की पारी के दौरान 5 चौके और 5 छक्के लगाए. इस दौरान उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 2000 रन भी पूरे किए. ईशान ने 1,345 गेंद में 2,000 रनों का आंकड़ा छुआ. वह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में तीसरे सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस रिकॉर्ड लिस्ट में अभिषेक शर्मा पहले नंबर पर और पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव दूसरे नंबर पर हैं. ईशान किशन के नाम टी20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में किसी भारतीय द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हो गया है. उन्होंने 2026 में 1,165 रन बनाए हैं. उन्होंने 1 नवंबर, 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ा।

एक दिन में 1 लाख करोड़ का पेमेंट, MDR चार्ज से पहले UPI का धमाका

नई दिल्ली। भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है. हर कोई छोटी- बड़ी हर तरह की पेमेंट के लिए फोन पे, गूगल पे या किसी और एप का ही इस्तेमाल करता है. क्योंकि ये आसान होता है और बार-बार एटीएम के चक्कर नहीं काटना पड़ते हैं. इसी के चलते अक्टूबर 2026 में UPI ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस महीने में हर रोज यूपीआई के जरिए पहली बार करीब 1 लाख करोड़ रुपये की रकम का लेन देन किया गया है. त्योहारों के सीजन में खरीदारी बढ़ने से UPI के इस्तेमाल में तेजी आई है. ये तेजी तब है जब सरकार जल्दी ही यूपीआई पेमेंट्स पर MDR चार्जेस लगाने वाली है.नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में UPI के जरिए कुल 25.47 अरब यानी करीब 2,547 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए. इन ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 31.53 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. पिछले साल अक्टूबर 2025 में UPI से 20.7 अरब ट्रांजैक्शन हुए थे. इस तरह एक साल में ट्रांजैक्शन की संख्या में करीब 23% की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, लेन-देन की कुल रकम में 16% का इजाफा हुआ है.अक्टूबर में UPI के जरिए हर रोज करीब 82.2 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए. ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

10 ग्राम सोने के बराबर पहुंचेगी 1 किलो चांदी की कीमत!



नई दिल्ली। सोना और चांदी के बाजार में पिछले कुछ समय से लगातार हलचल देखने को मिल रहा है. कुछ समय पहले तक चांदी की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही थीं और निवेशकों को इससे अच्छी कमाई की उम्मीद थी. लेकिन अब बाजार का रुख बदल गया है, अब इसकी कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है. हालात ऐसे हो गए हैं कि एक किलो चांदी और 10 ग्राम सोने की कीमत के बीच का अंतर काफी तेजी से कम हो रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में एक किलो चांदी की कीमत 10 ग्राम सोने के बराबर पहुंच सकती है?

सोने और चांदी की कीमतों में कितना अंतर?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार को चांदी का वायदा भाव 10,500 रुपये गिरकर 1,78,900 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया. वहीं, सोने का वायदा भाव 4,347 रुपये टूटकर 1,38,419 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. इस तरह दोनों की कीमतों के बीच करीब 40,500 रुपये का अंतर बचा है.यानी मौजूदा सोने की कीमत के बराबर पहुंचने के लिए चांदी को अभी करीब 22.6% और सस्ता होना होगा. हालांकि, यह तभी मुमकिन होगा जब सोने की कीमत स्थिर रहे.

अपने रिकॉर्ड स्तर से कितनी नीचे आई चांदी?

जनवरी 2026 में M C X पर चांदी की कीमत 4,20,048 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी. लेकिन शुक्रवार के भाव के हिसाब से यह अपने उच्चतम स्तर से करीब 57% नीचे आ चुकी है. दूसरी तरफ, सोना भी जनवरी में बने 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड भाव से करीब 23% गिर चुका है.अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है. शुक्रवार को स्पॉट सिल्वर करीब 6% टूटकर 49 डॉलर प्रति औंस पर आ गई, जबकि सोना करीब 3,875 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था.

खतरे में लिस्टेड कंपनियों का प्रशासन

विरासत की जंग में उलझा 115 साल पुराना टीवीएस ग्रुप



नई दिल्ली। वेणु श्रीनिवासन परिवार में उत्तराधिकार को लेकर चल रहे विवाद से टीवीएस होल्डिंग्स लिमिटेड और टीवीएस मोटर कंपनी के संचालन एवं प्रबंधन संबंधी जोखिम पैदा हो सकते हैं। हालांकि, स्वामित्व के हस्तांतरण और प्रबंधन में बदलाव औपचारिक कॉरपोरेट प्रक्रियाओं के जरिए किए गए हैं। कॉरपोरेट संचालन और प्रशासन पर सलाह देने वाली कंपनी इनगवर्न ने रविवार को यह बात कही।इस विवाद का विश्लेषण करने वाली अपनी रिपोर्ट में इनगवर्न ने कहा कि अल्पांश शेयरधारकों की मुख्य चिंता परिवार की निजी संपत्ति के बंटवारे को लेकर नहीं है, बल्कि यह है कि उत्तराधिकार के अधिकार, प्रवर्तकों का नियंत्रण और प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाएं कितनी स्पष्ट हैं, उन्हें कितनी कानूनी निश्चितता हासिल है और उनका खुलासा कितनी पारदर्शिता से किया गया है।

कारोबार के बंटवारे को लेकर मतभेद

वेणु श्रीनिवासन परिवार में संपत्ति और कारोबार के बंटवारे को लेकर मतभेद सामने आने के बाद यह विवाद अक्टूबर में सार्वजनिक हुआ।वेणु श्रीनिवासन टीवीएस होल्डिंग्स के चेयरमैन हैं। श्रीनिवासन का कहना है कि उन्होंने अपनी निजी संपत्तियों और परिवार के कारोबार को पारदर्शी तरीके से अलग कर दिया है। वहीं, उनकी पत्नी मल्लिका श्रीनिवासन और बेटी लक्ष्मी वेणु का कहना है कि परिवार के भीतर संपत्ति का कोई आर्थिक समझौता नहीं हुआ है।इस विवा उसके कारोबार या पहले की तरह कामकाज जारी रखने की क्षमता पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

इनगवर्न ने क्या कहा?

हालांकि, इनगवर्न के अनुसार, शेयर बाजार को दी गई सूचना में एमओयू की शर्तों का खुलासा नहीं किया गया था और न ही यह स्पष्ट किया गया था कि परिवार के बीच संपत्ति को लेकर पूरा आर्थिक समझौता हो चुका है। मल्लिका श्रीनिवासन और लक्ष्मी वेणु सार्वजनिक रूप से कहती रही हैं कि मार्च 2024 के एमओयू को परिवार के आर्थिक हितों के निपटारे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।दूसरी ओर, वेणु श्रीनिवासन का कहना है कि संबंधित संपत्तियां उनकी निजी संपत्ति हैं और उन्हें अपनी इच्छानुसार उनका इस्तेमाल करने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा है कि टीवीएस समूह के व्यापक समझौते के संदर्भ में 10 दिसंबर, 2020 को उनके दोनों बच्चों के बीच संपत्तियों का बंटवारा निष्पक्ष और समान तरीके से किया गया था। इनगवर्न ने कहा कि वह परिवार के सदस्यों के बीच एक-दूसरे के दावों पर फैसला नहीं दे रही है और न ही निजी व्यवस्थाओं की वैधता, निष्पक्षता या उन्हें लागू किए जाने की क्षमता पर कोई राय दे रही है। उसका आकलन केवल सूचीबद्ध कंपनियों के संचालन एवं प्रशासन, सूचना के खुलासे और अल्पांश शेयरधारकों पर इसके असर तक सीमित है।

PNB Scam: 6 अफसरों की ID चुराकर फ्रॉड, कुर्सी खाली देखते ही बैठ जाती थी

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की एक ब्रांच में करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. बैंक की सेक्टर पाई-1 ब्रांच में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी पर आरोप है कि उसने 6 बैंक अधिकारियों की लॉगिन ID का इस्तेमाल करके ग्राहकों के खातों से पैसे ट्रांसफर किए. इस मामले में हाल ही में CCTV फुटेज भी सामने आया है. इसमें महिला कर्मचारी दूसरे अधिकारियों की खाली कुर्सियों पर बैठकर उनके कंप्यूटर चलाती दिखाई दी. मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है.न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक बैंक की शुरुआती जांच में ग्राहकों के खातों से करीब 10.24 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन का पता चला है. हालांकि, कुछ ग्राहकों का दावा है कि उनके सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से करीब 35 करोड़ रुपये गायब हैं. बताया जा रहा है कि इनमें कई किसान भी शामिल हैं. इन किसानों ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन के बदले मिले मुआवजे की रकम बैंक में जमा की थी. बैंक की शिकायत के मुताबिक, महिला कर्मचारी दीपांशी शर्मा ने 6 अधिकारियों की लॉगिन ID का गलत इस्तेमाल किया.।

छत्तीसगढ़ शासन

सुशासन के संकल्प से

नवा रायपुर बन रहा

एजुकेशन हब

प्रबंधन | उद्यमिता | नवाचार

NSTI
नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट

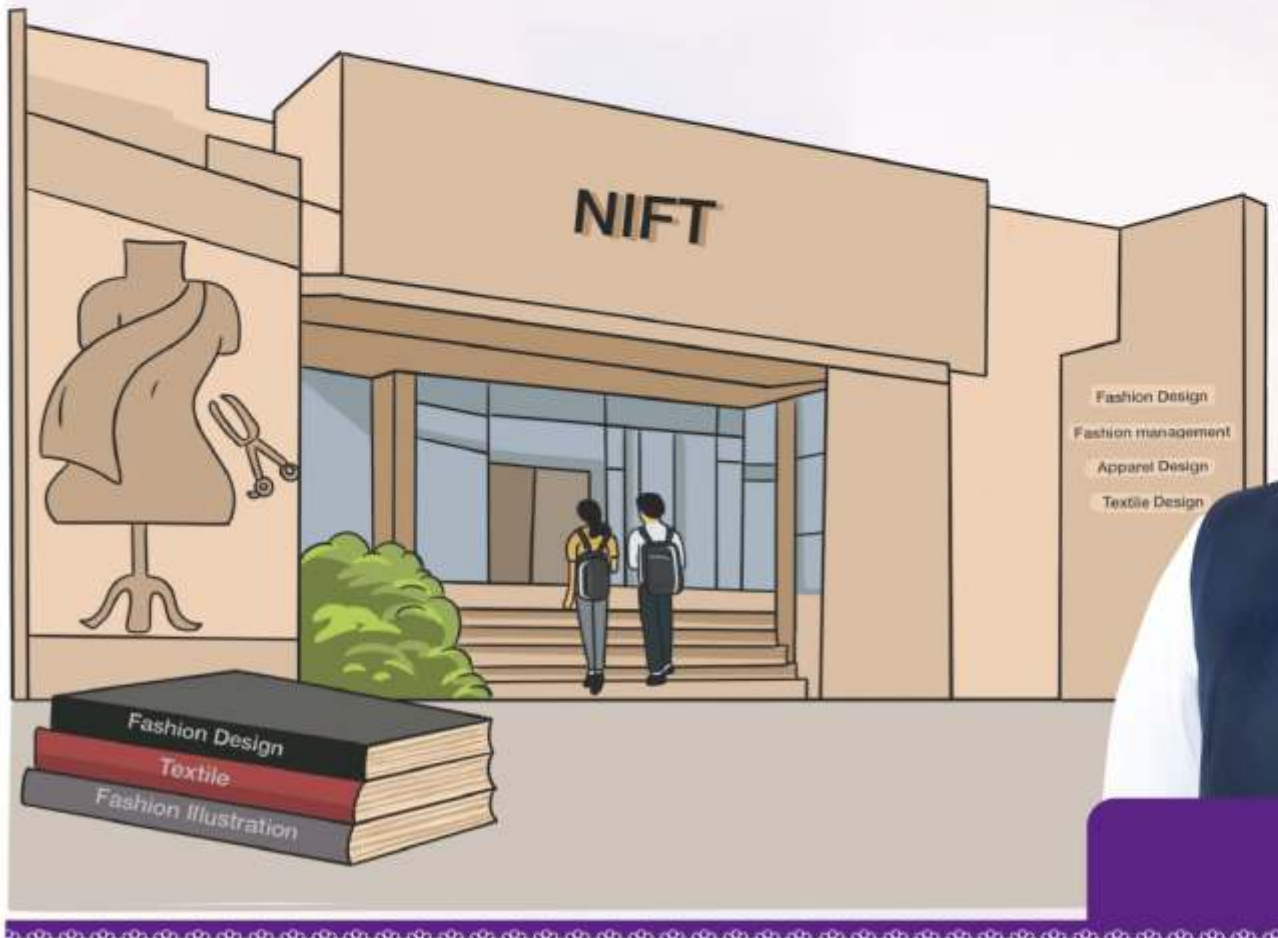
NIELIT
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी

NMIMS
नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज

NIFT
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी



NFSU
नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी कैम्पस





श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

SAMVAD- 14134/ 27

हमसे जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

सुशासन से समृद्धि की ओर

साप्ताहिक शहरसत्ता
हम दिखाएंगे आईना...



स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27